Colleges, the proposals are examined under Indian Medical Council (Amendment) Act, 1993. Opening and administration of ITIs fall uner the purview of respective State Govts./ UT Administrations.

(c) Authentic information is not available.

(d) and (e) Proposals for starting new technical education institutions from Northern States are under various stages of processing with All India Council for Technical Education.

Statement

Number of approved Engineering, Medical, ITI and Polytechnic in Northern and Southern States

	Number of Engg. Colleges	Number of Medical Colleges	Number of ITIs	Number of Polytechnics
1	2	3	4	5
SOUTHERN STATES				
1. Andhra Pradesh	12	10	331	53
2. Karnataka	14	14	185	33
3. Kerala	11	5	317	31
4. Pondichery	1	1	4	3
5. Tamil Nadu	38	10	302	44
TOTAL :	76	40	1139	164
NORTHERN STATES				
1. Delhi	5	4	42	11
2. Haryana	3	1	107	13
3. Himachal Pradesh	11	1	33	4
4. Jummu & Kashmir	1	2	32	4
5. Punjab	4	5	114	16
6. Rajasthan	7	5	64	16
7. Uttar Pradesh	20	9	272	88
8. Chandigarh	4	—	3	2
TOTAL :	45	27	667	154

केन्द्रीय विद्यालय

2346. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में आगामी पांच वर्षों के दौरान राज्यवार तथा नगरवार कितने नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपेक्षित मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ग) सरकार द्वारा प्रथम चरण में खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार और नगरवार संख्या क्या है और प्रत्येक विद्यालय में कितने विद्यार्थियों को दाखिला किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने प्रथम सूची में कुछ राज्यों के लिए अधिक प्रावधान दिया है जबकि कुछ राज्यों को सूची से निकाल दिया गया है, उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रथम सूची में शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) द्वितीय चरण की सूची कब तक जारी की जाएगी, उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से

(ङ.) केन्द्रीय विद्यालय, राज्यवार या नगरवार आधार पर खोले/आबंटित नहीं किए जाते । केन्द्रीय विद्यालय, उन क्षेत्रों में, जिनमें सिविल या रक्षा क्षेत्रों के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की बहुलता होती है तथा उपभोक्ता एजेन्सियों जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामील हैं की मांगों/सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं । इस प्रक्रिया में न तो किसी राज्य/ संघशासित क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलना निर्धारित किया गया और न ही किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र की अवहेलना की गई । सरकार ने अगले पांच वर्षों अर्थात 1993–98 के दौरान प्रतिवर्ष रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों में 20 केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है तथा परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जहां आवर्ती तथा अनावर्ती कुल व्यय प्रायोजक निकाय/परियोजनाओं द्वारा वहन किया जाना होगा वहां रुपी उचित पाए जाने वाले प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है । चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान, संगठन ने 24 केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए हैं, जिन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है । सामान्यतः प्रत्येक सैक्शन/कक्षा में 35 छात्र दाखिल किए जाते हैं ।

विवरण

1993–94 के दौरान 31 जुलाई, 1993 तक स्वीकृत किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रम० सं०	स्टेशन का नाम	स्वीकृत की गई कक्षाएं
आन्ध्र प्रदेश		पहली से पांचवीं तक
1.	गूटी, जिला अनंतपुर	
असम		
2.	वायुसेना स्टेशन, दिजान	"
बिहार		
3.	बरकाकाना, जिला हजारीबाग	"
4.	वायुसेना स्टेशन, दरभंगा	"
गुजरात		
5.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजीरा सूरत, परियोजना	"
हरियाणा		
6.	वायुसेना स्टेशन, मोहम्मदपुर (अहीर) जिला गुड़गांव	"
हिमाचल प्रदेश		
7.	नालेती, जिला कांगड़ा	"
केरल		
8.	आडोर, पाथानमथिट्टा जिला	"
कर्नाटक		
9.	विनोबा नगर हुबली, जिला धारवाड़	"
10.	मैसूर	"
मध्य प्रदेश		
11.	बालाघाट	"
12.	धार	"
13.	छतरपुर	"
14.	बारवाह, जिला खरगौन	पहली से आठवीं तक
15.	महासमुंद	पहली से पांचवीं तक
16.	छिन्दवाड़ा	"
17.	टी० एफ० आर० आई० जबलपुर परियोजना	"
महाराष्ट्र		
18.	अजनी, जिला नागपुर	"

उड़ीसा		
19.	सुंदरगढ़	
राजस्थान		
20.	बीवाड़, जिला अजमेर	पहली से आठवीं तक
त्रिपुरा		
21.	कैलाशाहार, जिला उत्तरी त्रिपुरा	पहली से पांचवीं तक
उत्तर प्रदेश		
22.	बलिया	"
23.	आप्टो इलेक्ट्रानिक फैक्टरी, देहरादून	"
दिल्ली		
24.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नांगली	"

गुजरात के महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाना

2347. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सरकारी महाविद्यालयों के विकास हेतु अनुदान की स्वीकृति करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक महाविद्यालय-वार कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी जारी कर दी गई है; और

(घ) स्वीकृत अनुदान राशि से कम राशि जारी करने का क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (श्रीमती शीलाजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा समापटल पर रख दी जाएगी ।

More elective subjects at plus two stage in Kendriya Vidyalayas

2348. SHRI DIGVIJAY SINGH :
SHRI SARADA MOHANTY :
SHRI N. E. BALARAM :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have since decided to start more and newer elective subjects at plus two stage in Kendriya Vidyalayas; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) According to information received from Kendriya Vidyalaya Sangathan there is no such proposal.

Modernisation of Technical Institutes

2349. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not been able to modernise and remove the obstacle in engineering and technological institutions in the country;

(b) whether Government have reviewed all the on going projects to modernise the institutes;

(c) if so, the details thereof; and

(d) how many schemes have been developed which had lost revenues ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) The Ministry has been providing financial support through its Direct Central Assistance scheme for Modernization & Removal of Obsolescence in the laboratories/workshops in Engineering and Technological Institutions in the country. From the 7th plan onwards, the Ministry has supported 2760 projects by releasing grant-in aid of Rs. 270.00 crores.

(b) and (c) The review/evaluation of all the